(ङ) क्या इस व्यवस्था के निजी क्षेत्र को सौंपे जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिससे कि रेलवे इस हानि को समाप्त करके लाभ अर्जित कर सके; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) विभागीय तौर पर संचालित कई खानपान यूनिटें भारी नुकसान पर चल रही हैं।

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1987-88, 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान भारतीय रेलों पर विभागीय खानपान यूनिटों की समग्र हानि क्रमशः 27.9 लाख रुपये, 71.5 लाख रुपये तथा 25.5 लाख रुपये थी।

(ग) और (घ) खर्च पर कड़ी निगरानी रखने, बिक्री अभियान चलाने, कर्मचारी को पुनः काम पर लगाने आदि जैसे कई उपाय किये गए हैं। कई विभागीय यूनिटों को लगातार नुकसान हो रहा है।

(ङ) और (च) सभी विभागीय खानपान यूनिटों को प्राइवेट क्षेत्र को सौंपने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु कुछ ऐसी विभागीय खानपान यूनिटों का गैर विभागीकरण करने का प्रस्ताव है जो नुकसान पर चल रही हैं।

देश में इस्पात की आवश्यकता

927. श्री रणजीत सिंह :

डा० जितेन्द्र कुमार तैर :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस्पात की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने हेतु इस्पात का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार जो कदम उठाने का विचार रखती है, उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो 1995 के अन्त में देश में इस्पात की मांग कितनी होगी;

(ग) क्या सरकार इस मांग को पूरा करने के लिए देश में इस्पात के उत्पादन की व्यवस्था कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क), (ग) और (घ) देश में इस्पात की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न उपायों द्वारा समय-समय पर इस्पात के उत्पादन को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:—

—वर्धित उत्पादन प्राप्त करने के लिए इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण और संयंत्र और उपस्करों का उन्नत अनुरक्षण।

—इस्पात संयंत्रों को आदानों विशेष रूप से कोयले और बिजली की सप्लाई का प्रबोधन, ताकि बिना व्यवधान के उत्पादन सुनिश्चित किया जा सके।

—विद्युत चाप भट्ठी इकाइयों को अपनी क्षमता वार्षिक 2.5 लाख टन तक बढ़ाने की अनुमति।

—निजी क्षेत्र में भारी क्षमता वाले नए इस्पात संयंत्रों की स्थापना की अनुमति देना।

—विशेष रूप से विनिर्दिष्ट श्रेणियों की शेष मांग को आयात से पूरा किया जाएगा।

(ख) लोहा और इस्पात उद्योग से संबंधित कार्यकारी दल द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार आठवीं योजना के अन्त में तैयार इस्पात की मांग 220 लाख टन होगी।

दिल्ली में फ्लाई ओवरों का निर्माण

928. श्री लक्ष्मण कुमार बिरला :
श्री तुफरान आलम :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "अर्बन आर्टस् कमीशन" ने राजधानी में फ्लाई ओवरों के निर्माण